



अर्थव्यवस्था में एक नई जान

देश में मैन्युफैचरिंग को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17 फीसदी कर दिया था, जबकि नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए इसको घटाकर 17 फीसदी पर ला दिया था, जो दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से कम है।

नवीन सिंह।

संकट के इस दौर में सुकून देने वाली एक खबर यह है कि चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैचरिंग इकाई लगाने की इच्छुक लगभग 1000 कंपनियों ने भारत सरकार से संपर्क साधा है। इनमें कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेज, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय संवाद में हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो कोरोना संकट से तबाह दिख रही हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी। जब चीन में कोरोना के असर के चलते विदेशी कंपनियों का कामकाज ठप पड़ा था, तब कई विशेषज्ञों ने यह बात कही थी कि भारत के लिए एक बड़ा अवसर पैदा होने जा रहा है। पिछले दिनों विभिन्न

राज्यों के मुखंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ओर इशारा करते हुए कहा था कि राज्य अगर रिफॉर्म करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो इस संकट को हम बहुत बड़े अवसर में बदल सकते हैं।

दरअसल आज की तारीख में जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैचरिंग हब के रूप में देखती हैं। इनमें पहले दो मुल्कों के पास जमीन की जबकि तीसरे के पास मैनपावर की काफी कमी है। भारत उन्हें मैन्युफैचरिंग के लिए पर्याप्त जमीन, प्रशिक्षित मैनपावर और अच्छा-खासा बाजार उपलब्ध करा सकता है। इन विदेशी कंपनियों के रुख को भांपकर भारत सरकार ने कोरोना संकट से उबरने के बाद मेक इन इंडिया

को गति देने के मकसद से अभी ही काम करना शुरू कर दिया है।

इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और वित्त मंत्रालय के साथ तमाम देशों में मौजूद भारत के दूतावास भी गंभीरता से लगे हुए हैं। देश में मैन्युफैचरिंग को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17 फीसदी कर दिया था, जबकि नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए इसको घटाकर 17 फीसदी पर ला दिया था, जो दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से कम है। इसके अलावा कुछ और बातें भी भारत के हक में जाती हैं। उसमें सबसे प्रमुख है सस्ते प्रशिक्षित श्रम की उपलब्धता। श्रम की लागत भारत में बांग्लादेश आदि की तुलना में काफी बड़ी है, फिर भी यह चीन से नीचे है।

हमारे देश में पैंतीस साल से कम उम्र की सबसे बड़ी जनसंख्या है और साइंस-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बहुत बड़ी तादाद हमारे पास है। कुल मिलाकर सस्ता श्रम, बड़ा टैलेंट पूल और रिकल्ड मैनपावर की उपलब्धता भारत को बाकी देशों की तुलना में काफी सस्ता और आकर्षक बना देती है।

दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले वाले भी भारत में ही हैं, जिसकी कमी चीन में एक बड़ी समस्या है। आज की तारीख में सबसे खास बात यह कि भारत ने कोरोना से लड़ाई में सबके प्रति सहयोगपूर्ण रवैया अपना कर पूरी दुनिया का भरोसा जीता है, जबकि चीन की स्थिति संदिग्ध हो गई है। पोस्ट-कोरोना दौर में हमें इसका भी लाभ मिल सकता है।

संवादों का प्रभाव

अशोक बोहरा। कैंकेयी के मन पर दासी के कुटिल संवादों का प्रभाव अपनी उच्चतम सीमा में पड़ चुका था। महारानी दृढ़ निश्चय कर अपनी उद्देश्य प्राप्ति की योजना तय कर चुकी हैं। महाराज दशरथ द्वारा पूर्व में दिए गए दो वरदानों को इस गंभीर क्षण में मांग लेने का वक्त आ चुका है। और ये भी निश्चित है कि उसमें पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और स्नेहसिक्त श्रीराम के लिए वनवास और वो भी चौदह वर्षों का ताकि भरत के मार्ग में कोई अवरोध ना रह जाए और वो अयोध्या के शासन में सम्राट के तौर पर अपनी भूमिका सिद्ध कर चुके हों। महाराज दशरथ की श्रवणेंद्रिय तक इस अकस्मात घड्यंत्र की ध्वनि पहुंच चुकी है। वह किसी बड़े अनिष्ट की आशंका से सिहर उठते हैं। महारानी ने अपने सिद्ध पराक्रम के दम पर उन्हें प्रसन्न कर जिन दो वचनों को भविष्य के लिए रक्षित कर रखा था, उनकी आशंका महाराज को स्वप्न में भी नहीं हो सकी, आखिर क्यों?

धर्म-दर्शन



संपादकीय

चिंता का विषय

भारत जैसे विकासशील देश में कोरोना जैसी आपदा के दौर में सोशल मीडिया का अनियंत्रित और अमर्यादित व्यवहार चिंता का विषय है। करीब एक महीना पहले दिल्ली और मुंबई में ऐसी ही एक खबर को लेकर प्रवासी मजदूरों को भारी परेशानी हुई थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और फर्जी खबरों को लेकर मीडिया को निर्देश जारी किया। कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के पीछे फर्जी खबरों की भूमिका पर चिंता जताते हुए मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया) को अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाने, घबराहट पैदा करने वाले और असत्यापित समाचारों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किया। अदालत ने कहा कि 'फर्जी खबरों के चलते प्रवासी मजदूरों के पलायन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के कल्याण को लेकर चिंतित हैं।' कोर्ट ने कहा कि 'हम विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस देश के सभी संबंधित पक्ष, अर्थात् राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकरण और नागरिक ईमानदारी से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी निर्देशों, सलाह और आदेशों का पालन करेंगे।' हाल के वर्षों में कई राज्यों में फर्जी खबरों को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है, लेकिन यह मामला अब भी नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। कई लोग इसके लिए सोशल मीडिया साइट्स को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं, पर यह कोई समाधान नहीं है। प्रतिबंध का रास्ता खुलते ही सूचना के कई गंभीर और विश्वसनीय स्रोत भी बंद हो जाएंगे, और अलोकतांत्रिक तो यह होगा ही। इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि लोग किसी भी जानकारी को पहले अपने विवेक की कसौटी पर परखें, उसके बाद ही उस पर विश्वास करें।

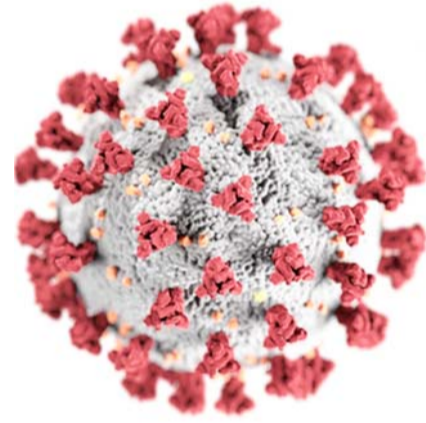
कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह के भ्रम और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जिससे लोगों के सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि किस बात को सच मानें और किसे झूठ।

लड़ाई में बाधाएं भी कम नहीं

किंशुक पाठक।

कोरोना वायरस ने हमारे जीवन को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। पूरी दुनिया आज इसके खिलाफ जंग लड़ रही है। लेकिन इस लड़ाई में बाधाएं भी कम नहीं हैं। एक तरफ समाज में सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अपनी जान पर खेलकर मानवता के पक्ष में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक तबका इसमें भी अपने स्वार्थ साधने में जुटा है। मीडिया का पुराना रोग फेक न्यूज कोरोना के दौर में कुछ ज्यादा ही गहरा गया है और इसने महामारी के खिलाफ लड़ाई को काफी मुश्किल बना दिया है। कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह के भ्रम और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जिससे लोगों के सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि किस बात को सच मानें और किसे झूठ। इससे कई तरह की व्यावहारिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं।

खबरों के साथ की जा रही इस छेड़खानी से परेशान होकर कई देशों ने फेक न्यूज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इटली के मीडिया ने लोगों तक कोरोना से जुड़ी सही खबरें पहुंचाने, उपचार के मामले में नीम-हकीमी के खतरों से बचाने और कोरोना जैसी आपदाओं की कवरेज के लिए प्रशिक्षित पत्रकारों की टीम



तैयार करने का रास्ता पकड़ा है। इस वैश्विक आपदा की खोजपूर्ण कवरेज के लिए खासकर इटली की कंपनी 'एडिनेट' के वर्किंग मॉडल पर विश्व मीडिया की नजर है। तीव्र संक्रमणकारी कोरोना वायरस के मामले में 'रिमोट न्यूजरूम' से कवरेज करने की 'एडिनेट' प्रविधि कारगर साबित हुई है।

इटली के सावोना नगर में स्कूलों, सिनेमाघरों, क्लबों, बाजारों की बंदी के बाद 'एडिनेट' प्रकाशन कंपनी के 'वास्त्रो जियोमाले' और जेनेवा-24 समाचार पत्रों ने तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के अलावा आशाजनक सकारात्मक खबरें और बचाव के

वैज्ञानिक उपाय भयाक्रांत पाठकों तक पहुंचाए। इंटरनेट की मदद से इंटरव्यू और लेख एकत्र करके पाठकों के समक्ष पेश किए गए। इससे पत्रकारों की भी संक्रमण से सुरक्षा हुई। जेनेवा के संक्रामक रोग प्रभारी मैतियो बासेती ने मीडिया के इस सहयोग को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया।

प्रामाणिक और विश्वसनीय खबरों के प्रकाशन ने इन समाचारपत्रों की साख का ग्राफ इस तरह ऊंचा चढ़ा दिया कि फेसबुक पर कोरोना वायरस खतरे से संबंधित एक खबर को सवा तीन लाख लोगों ने शेयर किया, जबकि समाचार पत्र में प्रकाशित एक लाइव साक्षात्कार को 25 लाख लोगों ने पढ़ा। फेक न्यूज की बाढ़ ने गूगल पर भी दबाव बढ़ा दिया है। उसने झूठी जानकारीयों से निपटने के लिए 65 लाख डॉलर (करीब 49 करोड़ रुपये) खर्च करने का फैसला किया। इस राशि के जरिए वह फेक्ट चेकर्स और गैर-लाभकारी संगठनों को बढ़ावा दे रहा है, जो कोरोना वायरस महामारी से जुड़े मामलों की तथ्यों के आधार पर जांच करेंगे। कंपनी लोगों को गलत खबरों और जानकारीयों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों, पत्रकारों और सिलेब्रिटीज की मदद ले रही है।

गूगल के मुताबिक उसके अभियान में भारत में बूम लाइव और नाइजीरिया में अप्रीका चेक के साथ साझेदारी करने में 'डाटा लीड्स' की मदद की जा रही है।

अपना ब्लॉग

सबसे ज्यादा फर्जी खबर

मोहन। वॉट्सऐप ने भी इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लॉकडाउन के समय व्हाट्सऐप लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन मामले का दूसरा पहलू यह है कि सबसे ज्यादा फर्जी खबरें भी यहीं प्रसारित की जा रही हैं। ऐसे में वॉट्सऐप ने कड़ा कदम उठाते हुए फॉरवर्ड मैसेज के लिए सीमा तय कर दी है। उसका दावा है कि इस कदम से उसके प्लैटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉरवर्ड किए जाने वाले फर्जी मैसेजेस में 70 प्रतिशत की कमी आई है। कंपनी का कहना है कि जब से हाइली फॉरवर्डेड मैसेजेस को आगे केवल 1 कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करने की सीमा तय की गई है, तब से इसमें कमी देखी जा रही है। वॉट्सऐप के एक प्रवक्ता ने कहा, 'वॉट्सऐप फेक और वायरल मैसेज को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। फेसबुक ने भी अपने प्लैटफॉर्म पर फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के कुछ फैसले लिए हैं। इसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर भी फर्जी खबरों को रोकने के लिए फिल्टर कर रहा है।

कोरोना का नाम बदलकर नहीं डरोना कर दिया है...



सूटिकू नवताल-5338					
7	8	6	1	5	2
	9		8		3
1		6	9	7	
	3	8	2	1	
2	7	5		6	3
		5	7	2	8
		9	7	4	6
8			2		5
4	2		5	9	1
2	9	3	1	4	8
3	6	1	2	8	7
4	7	5	9	6	3
5	7	4	1	6	2
1	3	6	9	4	8
9	8	2	7	3	5
6	2	8	4	7	1
4	5	3	6	2	9
7	1	9	8	5	3